THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) and (b). Arrangements were made by Government for distribution of free-sale sugar to all categories of consumers during festival months of September and October, 1980 through State Government agencies at prices around Rs. 6 per kg. under the Scheme of Voluntary offer made by the factories to deliver sugar at a fixed ex-factory price of Rs. 450 per quintal excluding excise duty. By and large, sugar was made available under this scheme at a reasonable price. However, there were some press reports about charging of higher prices for sugar by traders at some places about which Government has no direct information.

(c) and (d). The special arrangements made for distribution of free-sale sugar at fixed prices under the voluntary offer of the industry has come to an end on 15th November, 1980 and sugar is available in the open market through normal trade channels, as in the past, under the existing policy of dual price control on sugar under which 35 per cent of the total production is being released for free sale in the open market. The price of sugar depends on the total availability, which is dependent on production.

कृषि उत्पाद के लिये कम समर्थन मूल्य

*9. श्री दौलत राम सारण :
श्री नित्यानन्द मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान खरीफ और आगामी रबि फसल के दौरान किन-किन कृषि-उत्पादों का समर्थन मूल्य घोषित करने का सरकार का विचार है और इसका आधार क्या है

(ख) क्या अब तक घोषित खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य किसान संगठनों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बहुत कम बताया जा रहा है और यदि हां, तो क्या किसान संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इनके समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जायेगी ;

(ग) क्या किसान तथा उनके संगठन अपनी बुवाई से पूर्व अपने उत्पाद के समर्थन मूल्य की घोषणा की मांग कर रहे हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक (गैर-कृषि) वस्तुओं के मूल्यों के बीच समानता का आधार अपनाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) सरकार ने धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी तथा दलहन (तुर मूंग तथा उड़द) व कपास, कच्ची पटसन, साबुत मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों तथा गन्ने की वर्तमान खरीफ फसलों के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी है। गेहूं, जौ तथा सरसों की आगामी रबी फसलों के लिए खरीद/समर्थन मूल्यों की घोषणा अभी की जानी है। ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत के उपलब्ध आंकड़ों, प्रतियोगी फसलों के आकलित मूल्यों, आदान मूल्यों, उत्पादन एवं मूल्य प्रवृत्ति, व्यापार की शर्तों आदि में हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखती है।

(ख) कृषि उत्पादों के खरीद/समर्थन मूल्यों की घोषणा करने से पहले सरकार ने किसान संगठनों, राज्य सरकारों

तथा अन्य संबंध रखने वालो के विचारो पर पूरी तरह से विचार किया है । पहले से ही घोषित खरीद/समर्थन मूल्यो मे कोई परिवर्तन करने का विचार नही है ।

(ग) किसान तथा किसान संगठन बुवाई से पूर्व अपने उत्पाद के समर्थन मूल्यो की घोषणा कराने की माग कर रहे हैं । इस वर्ष ऐसा करना संभव नही हो सका है क्योकि जून के महीने मे उर्वरक तथा डीजल की कीमतो मे भारी वृद्धि के कारण कृषि मूल्य आयोग को पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । भविष्य मे सरकार यथा संभव शीघ्र ही खरीद/समर्थन मूल्यो की घोषणा करना चाहती है ।

(घ) कृषि मूल्य आयोग को खरीद/समर्थन मूल्यो के उचित स्तर की सिफारिश करते समय कृषि एव गैर-कृषि वस्तुओ के बीच व्यापार की शर्तों में हुए परिवर्तनो को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है ।

Radical Changes in Education

*10 SHRI KRISHNA PRATAP SINGH: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state,

(a) whether Government are thinking of making radical changes in the education system;

(b) whether it is a fact that the present education system of 10 + 2 + 3 has not brought the desired results; and

(c) what are the details of the proposals in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Houses for the Scheduled Castes and Backward Classes in Delhi

*11. SHRI HIRALAL R PARMAR: SHRI RAM LAL RAHI:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state

(a) whether Government have any scheme to provide housing facility to homeless persons belonging to Scheduled Castes, economically backward class and labourers living in Delhi Territory for a long time; and

(b) if so, the outlines thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) (a) and (b). Delhi Administration has reported that although no separate scheme as such for providing housing facilities to the homeless persons belonging to Sheduled Castes, economically backward class and labourers living in Delhi territory for a long time is in operation, there are the following schemes running:—

(1) Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers

This Scheme is applicable to certain employees within the meaning of The Indian Factories Act, 1948.

(2) House-sites-cum-Hut Construction Scheme for Landless Workers in Rural Areas.

This scheme relates to provision of house-sites for landless agricultural labourers, workers and artisan living in rural areas. The ceiling for